



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 295]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 13, 2009/माघ 24, 1930

No. 295]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 13, 2009/MAGHA 24, 1930

लोक सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2009

का.आ. 477(अ).—लोक सभा अध्यक्ष का भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन दिनांक 12 फरवरी, 2009 का निम्नलिखित विनिश्चय एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है:—

“माननीय लोक सभा अध्यक्ष के समक्ष

संसद भवन, नई दिल्ली

श्री अनंत गंगाराम गीते,

नेता,

शिव सेना संसदीय दल (लोक सभा)

128, संसद भवन, नई दिल्ली

.....याची

बनाम

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील,

संसद सदस्य (लोक सभा),

दिल्ली का पता: 68, नॉर्थ एवेन्यू,

नई दिल्ली-110001

स्थायी पता : ग्राम और पोस्ट. जाम्ब, जिला-परभनी,

महाराष्ट्र ।

.....प्रत्यर्थी

के मामले में :

आदेश :

1. यह आवेदन लोक सभा में शिव सेना संसदीय दल के नेता श्री अनंत गंगाराम गीते द्वारा श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील, संसद

सदस्य, लोक सभा के विरुद्ध 28 जुलाई, 2008 को दाखिल किया गया, जिसमें इस आदेश के लिए प्रार्थना की गई है कि प्रत्यर्थी को इस आधार पर भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन वर्तमान लोक सभा का सदस्य होने और बने रहने से निरह किया जाए कि प्रत्यर्थी अपने दल के निदेश तथा विधेय के प्रतिकूल 21 जुलाई, 2008 को लोक सभा में प्रधानमंत्री द्वारा पेश किए गए विश्वास प्रस्ताव के दौरान मतदान से अनुपस्थित रहे ।

2. याची ने यह कहा है कि प्रत्यर्थी, जो लोक सभा का सदस्य है, शिव सेना के टिकट पर महाराष्ट्र राज्य के परभनी निर्वाचन क्षेत्र से मई, 2004 में निर्वाचित हुए थे तथा उनका नाम लोक सभा के रिकार्ड में शिव सेना की सदस्य सूची में शामिल है ।

3. याची के अनुसार शिव सेना संसदीय दल ने 20 जुलाई, 2008 को लोक सभा में प्रत्यर्थी सहित अपने सभी सदस्यों को 21 और 22 जुलाई, 2008 को सभा में उपस्थित रहने तथा केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् में विश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान करने के लिए एक तीन पंक्ति विधेय जारी किया था। विधेय की एक प्रति याचिका के साथ संलग्न की गई है ।

4. याची का मामला यह है कि शिव सेना द्वारा विधेय जारी किए जाने के बावजूद प्रत्यर्थी मतदान से अनुपस्थित रहा और इस प्रकार उसने दल के विधेय और निदेश का घोर उल्लंघन किया है । अतः याची के अनुसार, प्रत्यर्थी लोक सभा का सदस्य होने से निरह हो गए हैं और यह कि मतदान के दिन उनकी अनुपस्थिति को दल ने माफ नहीं किया है ।

5. लोक सभा अध्यक्ष को सम्बोधित 28 अगस्त, 2008 के एक पत्र के द्वारा प्रत्यर्थी ने यह तर्क दिया है कि वह स्वयं और उसके

परिवार के सदस्य "जबरदस्त तनाव में थे और असुरक्षित महसूस कर रहे थे", और उन्हें अपने और अपने परिवार के प्रति खतरे की आशंका थी जिसके लिए उन्हें पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई है और उक्त कारणों से उन्होंने याचिका पर अपनी टिप्पणियां देने के लिए दो सप्ताह का समय दिए जाने का अनुरोध किया था, जो उन्हें प्रदान किया गया।

6. 10 सितम्बर, 2008 के एक और पत्र के द्वारा प्रत्यर्थी ने और दो सप्ताह का समय मांगा "क्योंकि वह शिव सेना के राजनीतिक दल की मौजूदा गतिविधियों के कारण अत्यधिक व्यथित थे और इसलिए वह उसका सुविचारित उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं", यह समय भी उन्हें प्रदान किया गया।

7. तत्पश्चात्, 25 सितम्बर, 2008 को प्रत्यर्थी ने याचिका का उत्तर दाखिल किया जिसमें प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि उन्हें अपनी पार्टी से अपने नई दिल्ली निवास के पते पर अथवा स्थायी पते पर कोई व्हिप प्राप्त नहीं हुआ था न ही उनका फ़ैक्स, टेलीफोन, इंटरनेट के माध्यम से अथवा सेल फोन पर किसी भी समय याची के साथ कोई सम्पर्क हुआ था और उन्होंने उन्हें कोई व्हिप तामील किए जाने का स्पष्ट रूप से इन्कार किया। उन्होंने आगे बताया कि उन्हें अपनी पार्टी से कोई व्हिप अथवा व्हिप के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। अपने उत्तर में उन्होंने आगे तर्क दिया कि उन्हें उनकी पार्टी से निकाल दिया गया था और उन्हें शिव सेना का सदस्य नहीं माना गया था और यह कि वह बहुत उलझन में थे और इस प्रकार वह संसद के सत्र में भाग लेने नहीं आए थे। अपने उत्तर में प्रत्यर्थी ने लोक सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरहता) नियम, 1985 में अंतर्विष्ट संगत नियमों का अनुपालन नहीं किए जाने के कारण याचिका की गैर पोषणीयता के बारे में भी तर्क दिया है।

8. 1 अक्टूबर, 2008 को याची ने प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल उत्तर का प्रत्युत्तर दाखिल किया जिसमें यह तर्क दिया गया कि 20 जुलाई, 2008 को हुई शिव सेना की बैठक में शिव सेना दल के सभी सदस्यों को व्हिप जारी किया गया था जिसमें प्रत्यर्थी उपस्थित नहीं थे और यह कि व्हिप की एक प्रति उनके नई दिल्ली स्थित सरकारी निवास पर भेजी गई थी। प्रत्युत्तर के साथ याची ने शिव सेना के संसद सदस्यों के नामों की सूची की एक प्रति दाखिल की जिसमें यह दर्शाया गया है कि प्रत्यर्थी उपस्थित नहीं थे और यह कि व्हिप उनके सरकारी निवास पर भेजा गया था। याची ने आगे प्रत्यर्थी के पते वाले एक लिफाफे की एक प्रति संलग्न की है जिसमें कथित तौर पर प्रत्यर्थी को व्हिप का नोटिस तथा 20 जुलाई, 2008 को होने वाली बैठक संबंधी नोटिस की एक प्रति भी भेजी गई थी।

9. संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2 (1)(ख) में यह उपबंध है कि पैरा 4 और 5 के उपबंधों के अधधीन किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित सभा का कोई सदस्य, यदि वह ऐसे राजनीतिक दल, जिसका वह सदस्य है, की पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसी सभा में मतदान करता है या मतदान करने से विरत रहता है और ऐसा मतदान करने से विरत रहने को ऐसे राजनीतिक दल ने ऐसे मतदान या मतदान से विरत रहने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर माफ नहीं

किया है, तो वह सभा का सदस्य बने रहने के लिए निरह हो जाएगा। वर्तमान मामले में पैरा 4 और 5 के उपबंध लागू नहीं होते।

10. डा. महाचन्द्र प्रसाद सिंह बनाम सभापति, बिहार विधान परिषद् एवं अन्य (2004) 8 एससीसी 747 के विनिर्णय में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है कि दसवीं अनुसूची के अधीन "सभा के सदस्य की निरहता के मुद्दे पर निर्णय करने का अंतिम प्राधिकार सभा के सभापति या अध्यक्ष में निहित है। यह ध्यान देने योग्य है कि दसवीं अनुसूची में सभा के सभापति या अध्यक्ष को कोई विवेकाधिकार नहीं दिया गया है। उनकी भूमिका केवल संबद्ध तथ्यों को सुनिश्चित करने तक ही सीमित है। एक बार एकत्रित अथवा प्रस्तुत तथ्यों से यह प्रकट होने पर कि सभा के किसी सदस्य ने ऐसा कोई कृत्य किया है जो दसवीं अनुसूची के पैरा 2 के उप-पैरा (1), (2) या (3) की परिधि में आता है, तो निरहता लागू होगी और सभा के सभापति या अध्यक्ष को इस आशय का निर्णय लेना होगा।"

11. मैंने इस मामले में 1 अक्टूबर, 2008 को व्यक्तिगत सुनवाई की थी जिसमें याची तथा प्रत्यर्थी और उनके साथ उनके विद्वान वकील भी उपस्थित थे। उक्त व्यक्तिगत सुनवाई के कार्यवाही वृत्तांत इन कार्यवाहियों के रिकार्ड के भाग हैं।

12. 1 अक्टूबर, 2008 को हुई व्यक्तिगत सुनवाई के पश्चात् मैंने मामले की प्रकृति और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संतुष्ट था क्योंकि यह आवश्यक तथा समीचीन था कि इस याचिका को लोक सभा की विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाए ताकि वह इस पर आरंभिक जांच करके तत्संबंधी रिपोर्ट सौंप दे तथा मैंने तदनुसार यह आदेश पारित किया।

13. विशेषाधिकार समिति ने 5 जनवरी, 2009 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह टिप्पणी की थी कि याची प्रत्यर्थी को वस्तुतः व्हिप तामील कराए जाने को सिद्ध नहीं कर पाया है और प्रत्यर्थी का यह तर्क भी गलत था कि वह पार्टी से निष्कासित होने के कारण लोक सभा सत्र में भाग नहीं ले सका।

14. रिपोर्ट को प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् मैंने इस मामले में 11 फरवरी, 2009 को एक और सुनवाई की, जिसमें याची उपस्थित हुआ था तथा प्रत्यर्थी भी अपने विद्वान वकील के साथ उपस्थित हुआ था। सुनवाई में याची ने यह स्वीकार किया कि प्रत्यर्थी को व्हिप तामील नहीं कराया जा सका क्योंकि वह मिल नहीं पाए थे तथा पार्टी के पास प्रत्यर्थी का कोई संपर्क सूत्र नहीं था परंतु उनको कार्यवाही की जानकारी थी, इसलिए उन्हें निरहित किया जाना चाहिए। प्रत्यर्थी ने अपने विद्वान वकील के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रतिवाद किया कि याचिका सुनवाई करने योग्य नहीं थी क्योंकि व्हिप को तामील कराए जाने संबंधी कोई साक्ष्य नहीं था और यह कि प्रत्युत्तर के साथ संलग्न दस्तावेज असली नहीं थे और उन्होंने निवेदन किया कि पूरी कार्यवाही मूल संकल्पना/संदर्भ से परे है और याचिका को रद्द किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत सुनवाई की कार्यवाही का पूर्ण उल्लेख उसके कार्यवाही वृत्तांत में किया जाएगा जिसे इन कार्यवाहियों के अभिलेख में रखा जाएगा।

15. अभिवचनों तथा व्यक्तिगत सुनवाई में किए गए अनुरोधों के आधार पर तथा विशेषाधिकार समिति की आरंभिक जांच की

रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह निर्णय लिया जाना है कि क्या प्रत्यर्थी को 21 और 22 जुलाई, 2008 को लोक सभा की बैठकों में उपस्थित होने तथा प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान करने का कोई दिशा-निर्देश दिया गया था जैसाकि याची ने प्रतिवाद किया था तथा क्या उनकी अनुपस्थिति पार्टी द्वारा जारी किए गए व्हिप और दिशा-निर्देश के विपरीत थी।

16. माननीय उच्चतम न्यायालय ने किहोता होलोहोन बनाम जैचिल्लू तथा अन्य (ए.आई.आर.-1993 एससी 412) के अपने निर्णय में यह टिप्पणी की है कि दसवीं अनुसूची के पैरा 2 (1) (ख) द्वारा यथा अनुध्यात निदेश को लिखा जाना तथा सदस्यों को जारी किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार से, यह विचार किया जाना भी आवश्यक है कि क्या प्रत्यर्थी को तामिल कराए जाने का स्पष्ट साक्ष्य है और यदि नहीं है, तो इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए परिस्थितियों की समग्रता और मामले के सत्याभास पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या प्रत्यर्थी को वस्तुतः दिशा-निर्देश जारी किये गये थे अथवा नहीं।

17. याची द्वारा ही किए गए निवेदनों से यह प्रतीत होता है कि शिव सेना का प्रत्यर्थी के साथ लम्बे समय से कोई भी संपर्क नहीं था तथा याची ने यह स्वीकार किया कि प्रत्यर्थी ने 20 जुलाई, 2008 को आयोजित बैठक में भाग नहीं लिया था तथा यह कि वह प्रत्यर्थी को व्हिप जारी किए जाने को सिद्ध नहीं कर सका बल्कि केवल यही सिद्ध कर सका कि व्हिप उनके नई दिल्ली स्थित सरकारी पते पर भेजा गया था।

18. वर्तमान मामले में यह स्वीकार किया गया है कि प्रत्यर्थी 20 जुलाई, 2008 को शिवसेना संसदीय दल की बैठक में उपस्थित नहीं था जिससे कि उसे बैठक में दल के किसी भी निर्णय की सूचना दी जा सकती और न ही उसे उस बैठक में कोई व्हिप जारी किया गया था तथा याची ने यह स्वीकार किया कि वह प्रत्यर्थी को व्हिप जारी किए जाने को सिद्ध नहीं कर सकता है।

19. इस बात पर ध्यान दिया जाना है कि प्रत्यर्थी शुरू से ही व्हिप प्राप्त होने से इंकार करता रहा है तथा साथ ही उसने अपने और अपने दल के बीच किसी भी तरह के संपर्क से इंकार किया है तथा यह प्राख्यान दिया है कि उसने दल की किसी भी बैठक में कभी भी भाग नहीं लिया और न ही दल से विशेष सत्र में मतदान करने से संबंधित कोई भी सूचना प्राप्त की और याची द्वारा प्रत्यर्थी पर वास्तविक व्हिप जारी किए जाने को सिद्ध करने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया था। नई दिल्ली के सरकारी निवास के पते पर व्हिप जारी किए जाने को सिद्ध करने का भी कोई प्रयास नहीं किया गया।

20. उपलब्ध सामग्री से यह प्रतीत होता है और जैसा कि याची द्वारा अपनी व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए निवेदन से यह पुष्ट होता है कि प्रत्यर्थी का दल के साथ लंबे समय से कोई भी संपर्क नहीं था और यह कि वह 20 जुलाई, 2008 को आयोजित बैठक में उपस्थित नहीं था। इसलिए मेरी राय में याची को यह सिद्ध करने के लिए कदम उठाने चाहिए थे कि क्या विशेष सत्र के लिए मतदान के तरीके से संबंधित दल के निवेश वाला कोई भी दस्तावेज अथवा व्हिप वास्तव में प्रत्यर्थी पर जारी किया गया था।

21. अतः यह प्रश्न उठता है कि क्या शिवसेना संसदीय दल, जिसके टिकट पर प्रत्यर्थी निर्वाचित हुआ था, द्वारा 21 और 22 जुलाई, 2008 को लोक सभा में चर्चा किए गए विश्वास प्रस्ताव पर मतदान करने से संबंधित कोई भी निर्देश जारी किया गया था।

22. जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(ख) द्वारा यथाविचारित निदेश लिखित में होना चाहिए तथा सदस्यों को जारी किया जाना चाहिए। इसी को देखते हुए, विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन और 11 फरवरी, 2009 को सुनवाई के दौरान किए गए निवेदनों सहित मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मेरी यह राय है कि याची संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(ख) की अपेक्षानुसार प्रत्यर्थी पर किसी भी विधि सम्मत निदेश को तामिल किए जाने को सिद्ध करने के लिए कोई भी विश्वसनीय साक्ष्य और यूँ कहें कि कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया।

23. याची ने अपने प्रत्युत्तर और अपने निवेदन में विश्वास प्रस्ताव पर शिव सेना संसदीय दल के रुख के बारे में जनता की जानकारी का उल्लेख किया। परंतु व्हिप जारी करने के बारे में मीडिया में प्रकाशन के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही इसके लिए कोई प्रयास किया गया था। इसके अलावा जब निर्णय लिए जाने के लिए मुख्य तथ्यगत प्रश्न भारत के संविधान के पैरा 2(1)(ख) के अनुसार प्रत्यर्थी पर व्हिप जारी करने की तथ्यता और वैधता हो, जैसा कि वर्तमान मामले में है, जो ऐसे मामले को मीडिया का हवाला देकर सिद्ध नहीं किया जा सकता है, जिसकी विषय-वस्तु प्रस्तुत नहीं की गई है और यहां तक कि इसको सिद्ध करने का प्रयास तक नहीं किया गया है।

24. इस प्रकार, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के दृष्टिगत विधि के अनुसार मैंने यह नहीं पाया है कि प्रत्यर्थी ने ऐसा कोई कृत्य किया है जो भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(ख) की परिधि के अंतर्गत आता हो।

25. उपर्युक्त तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् मुझे लगता है कि याची याचिका में उल्लिखित तर्क सिद्ध नहीं कर पाए हैं और इसलिए इसे अस्वीकार किया जाता है।

नई दिल्ली,

12 फरवरी, 2009

ह/

सोमनाथ चटर्जी
अध्यक्ष।"

[सं. 46/26/2008/टी]

पी. डी. टी. आचारी, महासचिव

LOK SABHA SECRETARIAT NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2009

S.O. 477(E).—The following Decision dated 12 February, 2009 of the Speaker, Lok Sabha given under the Tenth Schedule to the Constitution of India is hereby notified:—

“BEFORE THE HON’BLE SPEAKER OF LOK SABHA, PARLIAMENT HOUSE, NEW DELHI

In the matter of :

Shri Anant G. Geete,
Leader,
Shiv Sena Parliamentary Party (Lok Sabha),
128, Parliament House,
New Delhi.

.....Petitioner

Versus

Shri Tukaram Ganpatrao Renge Patil,
Member of Parliament (Lok Sabha),
Delhi Address :
68, North Avenue,
New Delhi-110001.
Permanent Address :
At & Post Jamb, District-Parbhani,
Maharashtra.

...Respondent

Order :

1. This is an application filed on 28th July, 2008 by Shri Anant G. Geete, Leader of Shiv Sena Parliamentary Party in Lok Sabha against Shri Tukaram Ganpatrao Renge Patil, MP, Lok Sabha praying for an Order that the Respondent may be disqualified from being and continuing as a Member of the present Lok Sabha under the Tenth Schedule to the Constitution of India on the ground of his abstention from voting contrary to the direction and the whip of his Party during the Motion of Confidence moved by Prime Minister in Lok Sabha on 21 July, 2008.

2. It is stated by the Petitioner that the Respondent who is a Member of the Lok Sabha was elected in May 2004 from Parbhani constituency in the State of Maharashtra on Shiv Sena ticket and that the name of the Respondent appears in the list of Shiv Sena members in the records of Lok Sabha.

3. According to the Petitioner, Shiv Sena Parliamentary party on 20 July, 2008 issued a three-line Whip to all its members in the Lok Sabha, including the Respondent, to be present in the House on 21 and 22 July, 2008 and vote against the Motion of Confidence in the Union Council of Ministers. A copy of the whip has been set out in the Petition.

4. The Petitioner's case is that in spite of the whip having been issued by Shiv Sena, the Respondent abstained from voting in gross violation of the party's whip and direction. Therefore, according to the Petitioner, the Respondent has incurred disqualification for being a Member of Lok Sabha and that his abstention on the date of voting has not been condemned by the Party.

5. By a letter dated 28 August, 2008 addressed to the Speaker, Lok Sabha, the Respondent contended that he

himself and his family members were under “tremendous strain in mind and tense and as we are feeling insecure”, and he apprehended danger to him and his family for which he has been provided police protection and for the said reasons he requested for two week's time to furnish his comments on the Petition, which was granted to him.

6. By a further letter dated 10 September, 2008, the Respondent asked for further two week's time “as he was then very much disturbed due to present activities by the political party of Shiv Sena and therefore is not in a position to apply mind coolly to reply to the same”, which was also granted.

7. Thereafter on 25 September, 2008, the Respondent filed his reply to the Petition, in which the Respondent, contended that he had not received any whip from his Party at his New Delhi residence or at his permanent address nor he had any communication either by way of fax, telephone, internet or on cell-phone with the petitioner at any point of time and he specifically denied the service of the whip on him. He further stated that he had not received any whip or any information about the whip from his Party. In his reply, he has further contended that he was removed from his Party and was not treated as a Member of Shiv Sena and that he was very much confused and thus had not come to attend the Parliament Session. In his Reply, the Respondent has also contended about the non-maintainability of the Petition due to non-compliance with the relevant rules contained in the Members of Lok Sabha (Disqualification on Ground of Defection) Rules, 1985.

8. On 1 October 2008, the Petitioner filed a rejoinder to the Reply filed by the Respondent, wherein it was contended that whip was issued to all the members of Shiv Sena Party at its meeting held on 20 July, 2008 at which the Respondent was not present and that a copy of the whip was sent to his official residence at New Delhi. Along with the rejoinder, the Petitioner filed a copy of the list of names of the Shiv Sena Members of Parliament at which it is shown that the Respondent was not present and that the whip was sent to him at his official residence. The Petitioner has further enclosed a copy of an envelope with the address of the Respondent on the same, in which the notice of whip was allegedly sent to the Respondent and also a copy of the notice of the meeting to be held on 20 July, 2008.

9. Paragraph 2(1)(b) of the Tenth Schedule to the Constitution provides that subject to provisions of Paragraph 4 and 5, a Member of the House belonging to any political party shall be disqualified for being a Member of the House, if he votes or abstains from voting in such House contrary to any direction issued by the political party to which he belongs, without obtaining the prior permission of such political party or without obtaining the condonation of the political party for such voting or abstention within 15 days from the date of such voting or abstention. In the present case, the provisions of paragraphs 4 and 5 have no application.

10. In the decision of Dr. Mahachandra Prasad Singh *Versus* Chairman, Bihar Legislative Council and others (2004) 8 SCC 747; the Hon. Supreme Court has been pleased to observe that under the Tenth Schedule, "the final authority to take a decision on the question of disqualification of a Member of the House vests with the Chairman or the Speaker of the House. It is to be noted that the Tenth Schedule does not confer any discretion on the Chairman or Speaker of the House. Their role is only in the domain of ascertaining the relevant facts. Once the facts gathered or placed show that a Member of the House has done any such act which comes within the purview of sub-paragraphs (1), (2) or (3) of paragraph 2 of the Tenth Schedule, the disqualification will apply and the Chairman or the Speaker of the House will have to make a decision to that effect."

11. I gave a personal hearing in the matter on 1st October, 2008 at which the Petitioner was present as well as the Respondent along with his learned lawyers. The minutes of the said personal hearing are part of the record of these proceedings.

12. After the personal hearing given on 1st October, 2008, I was satisfied that having regard to the nature and circumstances of the case that it was necessary and expedient to refer the Petition to the Committee of Privileges, Lok Sabha for making a preliminary enquiry and for submission of a Report thereon, and I passed an Order accordingly.

13. On 5th January, 2009, the Committee of Privileges submitted its Report in which the Committee observed, *inter alia*, that the Petitioner has not been able to establish actual service of whip on the Respondent and that the Respondent's contention that he did not come to participate in the Lok Sabha Session as he had been expelled from the party was also not correct.

14. After the submission of the Report, I gave another personal hearing in the matter on 11th February, 2009 at which the Petitioner was present as well as the Respondent with his learned lawyers. At the hearing, the Petitioner admitted that the whip could not be served on the Respondent as he was not traceable and that the Respondent had not kept any contact with the Party but he was aware of the proceedings and should be disqualified. The Respondent through his learned lawyer, *inter alia*, contended that the Petition was not maintainable, that there was no evidence about the service of the whip and that the documents which have been annexed to the Rejoinder were not genuine and he submitted that the entire proceedings were misconceived and the petition should be rejected. The proceedings of the personal hearing will fully appear in the minutes thereof kept in the records of these proceedings.

15. On the basis of the pleadings and the submissions made at the personal hearing and after duly considering the Report of the preliminary enquiry of the Committee of Privileges, it has to be decided whether the

respondent was given any direction to attend the sittings of the Lok Sabha on 21st and 22nd July, 2008 and to vote against the Motion as contended by the Petitioner and whether his abstention was contrary to the whip and the direction issued by the party.

16. The Hon'ble Supreme Court has observed in its decision of *Kihota Hollohon Vs. Zachilhu & Ors.* (AIR 1993 SC 412) that a direction as contemplated by para 2(1)(b) of the Tenth Schedule is required to be in writing and issued to the Members. Thus, it is necessary to consider whether there was any clear evidence of service on the Respondent and if not, then, one has to consider the totality of circumstances and the plausibility of the case in coming to a finding whether directions were in fact issued to the respondent or not.

17. It appears from the submissions made by the Petitioner himself that the Shiv Sena Party has had no contact with the Respondent for a long time and the Petitioner admitted that the Respondent did not attend the meeting held on 20th July, 2008 and that he could not prove service of the whip on the respondent except that it was sent to his official address at New Delhi.

18. In the present case, admittedly, the Respondent was not present at the meeting of the Shiv Sena Parliamentary Party on 20th July, 2008 so that he could not have been informed of any decision of the Party at the meeting nor was he served with the whip at that meeting and the Petitioner admitted that he had nothing to establish that the whip was served on the Respondent.

19. It is to be noted that when from the very beginning the respondent has been denying the receipt of the Whip and also denied any connection between him and his Party and had asserted that he never attended any meeting nor received any communication from the Party regarding the voting at the Special Session, no effort was made by the Petitioner to prove the actual service of the whip on the respondent. About the service at the official residence at New Delhi, no attempt has been made to prove the same either.

20. From the materials on record, it appears and as confirmed by the Petitioner during his submission made at the personal hearing that the Party did not have any contact with the respondent for a long time and that he was not present at the meeting held on 20th July, 2008. Thus, in my view, the Petitioner should have taken steps to prove affirmatively that the whip or any document containing direction of the party regarding the manner of voting for the Special Session had in fact been served on the Respondent.

21. The question, therefore, arises whether any direction was issued by Shiv Sena Parliamentary Party, on whose ticket the Respondent was elected regarding the voting on the Motion of Confidence discussed in Lok Sabha on 21st and 22nd July, 2008.

22. As has been mentioned earlier, it has been held by the Hon'ble Supreme Court that a direction as contemplated by para 2(1)(b) of the Tenth Schedule is required to be in writing and issued to the Members. In view of the same, taking all the circumstances of the case including the Report of the Committee of Privileges and the submissions made during the hearing on 11th February, 2009 into account, I am of the opinion that the Petitioner has not been able to adduce credible or rather any evidence to prove the service of any lawful direction on the respondent in accordance with the requirement of paragraph 2(1)(b) of the Tenth Schedule of the Constitution.

23. The Petitioner in his Rejoinder as well as in his submission referred to the public knowledge about the stand of Shiv Sena Parliamentary Party on the Motion of Confidence. But no proof was adduced regarding the publication in the media about the issuance of the whip nor was any attempt made to do so. Further, when the main question of fact to be decided as in the present case, is the factum and validity of the service of the whip on the Respondent in accordance with the paragraph 2 (1) (b) of the Constitution of India, the same cannot be proved by

mere reference to the media, the contents of which have not been produced, far less having been attempted to be proved.

24. Thus, in the facts and circumstances of the case and in law, I do not find that the Respondent has done any such act, which comes within the purview of paragraph 2(1)(b) of the Tenth Schedule to the Constitution of India.

25. Taking into account the aforesaid, I find that that the Petitioner has not been able to establish the contentions made in the Petition and the same stands rejected.

Sd/-

SOMNATH CHATTERJEE

Speaker."

New Delhi :

The 12 February, 2009

[F. No. 46/26/208/T]

P. D. T. ACHARY, Secy.-General